भजनलाल सरकार ने विधानसभा में 6.10 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 संकल्पों में पढ़ा सरकार का विजन

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में 6.10 लाख करोड़ रुपए का तीसरा आम बजट 10 संकल्पों में पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाने, किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने, मेधावी छात्रों को 20 हजार रु. का ई-वाऊचर, परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी, स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने तथा असहाय, विमंदित, लावारिस मरीजों के फ्री इलाज की घोषणा की। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रु. किया। होमगार्ड्स के 5 हजार पद भी बढ़ाए गए है।

राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ का बजट आकार प्रस्तावित किया है। जो कि पिछले बजट से 52 हजार 360 करोड़ रु. ज्यादा है। बजट प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 5 लाख 25 हजार 740 करोड़ 34 लाख रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, राजस्व व्यय 3 लाख 50 हजार 50 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपये आंका गया है। सरकार ने वित्तीय संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हुए राजकोषीय घाटा 79 हजार 492 करोड़ 52 लाख रुपये रहने का अनुमान जताया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.69 प्रतिशत होगा। आर्थिक प्रगति के संकेत देते हुए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि, सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसकी पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। कर्मचारी अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए स्थायी दिव्यांग हो जाता है और वह नौकरी करने में असमर्थ है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। उन्होंने जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में राज्य सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। इसके साथ ही 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा। अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है।

देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी की घोषणा के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है।

इसी तरह किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा से मार्च-अप्रैल में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास है। मेधावी विद्यार्थियों को 20 हजार रुपए का ई-वाऊचर देने से भी इन तमाम परिवारों के बीच सरकार की पॉजिटिव ब्रांडिंग पहुंचाने की कोशिश है। वहीं स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारा लोगों के लिए कौतूहल व चर्चा का विषय छोड दिया है। इसी प्रकार बजट में लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने से भी महिला वर्ग को साधने का प्रयास है।

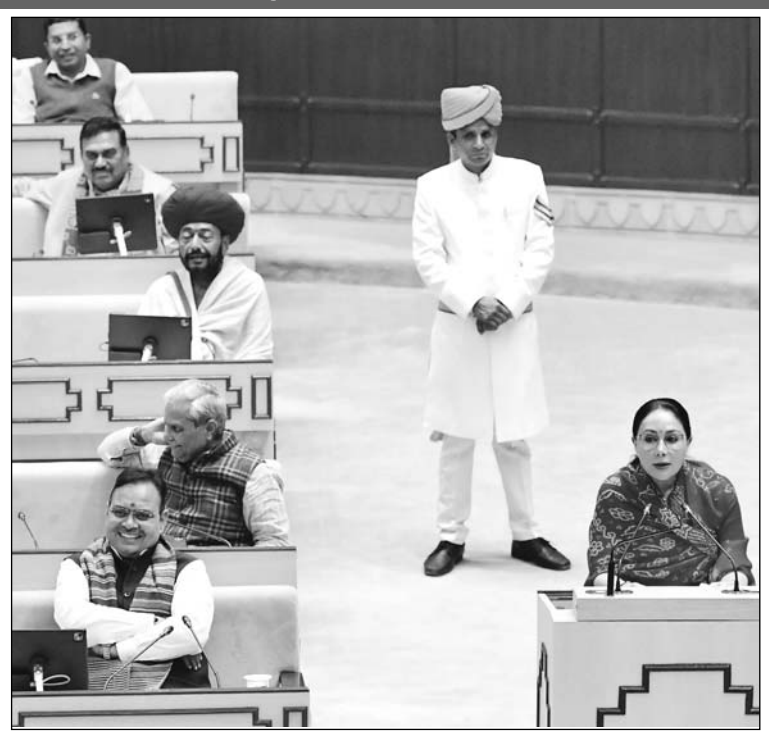

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तंज कसा, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सत्ता पक्ष ने ठहाके लगाए।

- 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी गठन, किसानों को 25 हजार करोड़ रु. का ब्याज मुक्त ऋण तथा लावारिस-विमंदितों के मुफ्त इलाज की घोषणा
- मेधावी विद्यार्थियों को 20 हजार रु. का ई-वाऊचर तथा स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारे की घोषणा
- महिला वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की

राजस्थान बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा

स्टांप ड्यूटी पर सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा; डी.एल.सी. दरें भी बदली

- हालांकि दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी
- सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा किया
- फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री करवाना महंगा हुआ

जयपुर (विसं)। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3 फीसदी बढ़ा दिया है। इस निर्णय का असर सीधे तौर पर स्टाम्प पेपर खरीदने पर देखने को मिलेगा। यही नहीं सरकार ने कुछ अलग-अलग कैटेगिरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव करते हुए पूरे प्रदेश में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी किया है। इन दोनों ही निर्णय से अचल सम्पत्तियों की रजिस्ट्री भी महंगी होगी।

बजट में सरकार ने बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले लोन या ऋण के लिए तैयार होने वाले डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले चार्ज को भी आधा कर दिया है। अभी तक ऐसे डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन की फीस 1 फीसदी लगती थी, लेकिन इसे कम करके आधी यानी 0.5 फीसदी कर दिया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी है। यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी। इसी तरह इन डॉक्यूमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को भी 0.25 फीसदी से आधा यानी (0.125 फीसदी) कर दिया है। वहीं इसकी अधिकतम सीमा को भी 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया है।

सरकार ने अब फार्म हाउस की जमीन की आरक्षित दरों (डी.एल.सी. रेट) में भी बढ़ोतरी की है। सरकार पहले फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य वहां की एग्रीकल्चर जमीन की दर 1.5 गुना मानते हुए रजिस्ट्री करती थी। लेकिन फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य एग्रीकल्चर जमीन का 3 गुना मानते हुए रजिस्ट्री की जाएगी।

इसी तरह कोई रिसोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री करवाता है तो पहले रिसोर्ट की जमीन का बाजार मूल्य वहां की कृषि भूमि का 2 गुना रेट मानकर करते थे, लेकिन अब ये दर वहां की कॉमर्शियल रेट का 75 फीसदी रेट मानकर रजिस्ट्री की जाएगी।बजट में सरकार ने दूसरे राज्य से गाड़ी (प्राइवेट व्हीकल) स्थायी रूप से लाने पर उसके रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले टैक्स पर छूट दी है। वर्तमान में इस तरह की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स अलग-अलग वाहनों (क्षमता के अनुसार) पर अलग-अलग दर से लगता है, जिस पर सरकार अभी 25 फीसदी तक छूट देती है। सरकार अब ऐसी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स पर दी जाने वाली छूट को 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने की घोषणा की है।

सीकर और झुंझुनूं में एयरपोर्ट का सर्वे, अरावली के किनारे बनेगी पक्की दीवार

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि अरावली पर्वतमाला का एक बड़ा हिस्सा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में आता है। करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से अरावली पर्वतमाला की करीब 4 हजार हैक्टेयर भूमि की जगह पर पक्की दीवार बनाई जाएगी। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। दिया कुमारी ने बजट में घोषणा की है कि, प्रदेश के सैनिक, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीरांगनाओं को सभी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए जोधपुर, शेरगढ़, टोंक, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनूं और श्रीगंगानगर में वॉर म्यूजियम, इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। पहले चरण में जोधपुर, शेरगढ़, झुंझुनूं और टोंक में 36 करोड की लागत से इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा।

सीकर और झुंझुनूं में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे की घोषणा की गई है। 8 जिलों में 3000 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने शेखावाटी के लिए यमुना जल परियोजना का काम जल्द शुरू होने की घोषणा की है। इस परियोजना पर 32000 करोड रुपए खर्च होंगे।

बजट में प्रदेश के लिए प्रमुख घोषणाएं...

- स्टेट हाईवे, फ्लाईओवर और एलिवटेड रोड के निर्माण व मरम्मत पर 1800 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- नॉन-पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों पर 1400 करोड़ तथा मिसिंग लिंग सड़कों पर 600 करोड़ रु. खर्च होंगे
- आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे
- विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्क के पहुंच मार्गों के विकास पर 400 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे
- आगामी वर्ष भी मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया
- राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों एवं शहरों में 2000 कैमरे स्थापित करने पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना का दायरा बढ़ाते हुए 5000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे
- एक हजार 92 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति
- आगामी वर्ष 600 टयूबवैल व 1200 हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित
- सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में ''सेंटर ऑफ एक्सिलेंस'' की स्थापना
- प्रदेश में 220 केवी के छह, 132 केवी के तेरह तथा 33 केवी के 110 जीएसएस निर्माण
- राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाईट्स लगेंगी
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में युवाओं को 10 लाख रु. तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान
- रानी लक्ष्मी बाई केंद्रों की 150 महाविद्यालयों में स्थापना, लगभग 25 हजार छात्रायें लाभान्वित
- 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाऊचर
- कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म
- प्रदेश के सभी विद्यालयों में टायलेट सुविधा तथा 1000 स्कूलों में एआई लैब की स्थापना
- खेलों राजस्थान ''यूथ गेम्स'' का ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर आयोजन
- प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मेंटल हैल्थ केयर सेल की स्थापना
- जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का आईपीडी टावर
- चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर की स्थापना
- मृतक के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क मोक्ष वाहिनी योजना
- 7500 आंगनबाड़ियों का नन्द घर के रूप में विकास
- खुड़ी-जेसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टयूरिज्म जोन तथा कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र
- 100 करोड़ रुपये भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण।
- झुंझुनूं, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों का संधारण
- जैसलमेर , जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट तथा झुंझुनूं में वार म्यूजियम।
- सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र की स्थापना
- आगामी वर्ष प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को वाट्सऐप प्लेटफोर्म पर भी शुरू
- 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को 'मिनी ई मित्र' के रूप में अधिकृत
- प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य 11 हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से होंगे
- आगामी वर्ष 50 हजार सोलर पंप संयंत्रों पर एक हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से होंगे
- विभिन्न कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान, लगभग 50 हजार कृषक लाभान्वित होंगे
- प्रदेश में 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50-50 गोदामों का निर्माण
- प्रदेश के चयनित जिलों में 2 हजार कृषकों , व्यापारियों व निर्यातकों को प्रशिक्षण
- नवगठित जिलों में जिला सहारकी उपभोक्ता भंडार तथा सभी जिलों में नवीन उपहार विक्रय केंद्र
- 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र तथा 25 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का क्रमोन्नयन
- अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट
- आगामी वर्ष 5000 गांवों में 2500 करोड़ रुपये की लागत से वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्य
- वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गैर-वन भूमि से एक हजार हेक्टेयर का लैंड बैंक

बजट प्रदेश की जनता पर डबल इंजन सरकार का दोहरा कुठाराघात : पायलट

सचिन पायलट

- सचिन पायलट ने कहा कि ''पहले केन्द्रीय बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई, अब राज्य सरकार ने भी लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है।''
- पायलट ने कहा कि ''हाईकोट में सरकार ने हफलनामे के माध्यम से स्वीकार किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बजट में मात्र 500 करोड़ रु. का प्रावधान दिखाता है कि सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है।''

जयपुर (कासं)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताया। पायलट ने कहा कि पहले केन्द्रीय बजट में भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की अनदेखी की गई और अब राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं पर पानी फेर दिया है।

पायलट ने कहा कि झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और सरकार हफलनामे के माध्यम से यह स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावजूद इसके राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना यह बताता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के चलते राजस्व घाटा बढ़ा है, सरकार को कर्ज लेना पडेगा, जिससे महंगाई बढेगी। सरकार ने शब्दों के मायाजाल से अपनी 2 वर्षो की नाकामी को छुपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के गत् वर्षो के बजट की भांति यह बजट भी धरातल पर उतरने वाला नहीं है।

पायलट ने कहा कि हाई टेक सिटी, आईटी सिटी और एयरो सिटी जैसी बड़ी घोषणाएं धरातल के बजाय केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। सरकार अपने पिछले बजट्स की उपलब्धियों पर पूरी तरह मौन साधे हुए है। प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का 4 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं होना और निजी क्षेत्र के रोजगार आंकड़ों का सार्वजनिक न करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। पायलट ने कहा कि नहरी क्षेत्रों में फार्म पौंड की सब्सिडी दो साल से बंद पडी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी न करना प्रदेश की गरीब जनता के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ के संभावित संकट और सोलर पार्कों के नाम पर राज्यवृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

पतंजलि शहद पर शोध प्रकाशित

हरिद्वार। पतंजलि अपने प्रत्येक उत्पाद में गुणवत्ता, शुद्धता और उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस प्रतिबद्धता को एक और सशक्त वैज्ञानिक मान्यता उस समय मिली, जब पतंजलि शहद पर किया गया विस्तृत शोध विश्वप्रसिद्ध ''एल्सवियर'' प्रकाशन के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल ''एप्लाइड फूड रिसर्च'' में प्रकाशित हुआ। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि जो कहता है, वही करता है और यह एक शाश्वत सत्य है। पतंजलि का उद्देश्य है इस देश को मिलावट के जहर से बचाना और पतंजलि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा ही समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य उत्पादों को लेकर लंबे समय से वैश्विक मंच पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है, किंतु अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित इस शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि भारत में भी विश्वस्तरीय अनुसंधान संभव है। यह उपलब्धि न केवल पतंजलि के लिए, बल्कि समूचे भारतीय उद्योग के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि पतंजलि शहद में किसी प्रकार की बाहरी शर्करा, सिंथेटिक सिरप या अवांछित रासायनिक अवशेष नहीं पाए गए हैं। पतंजलि के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुराग वार्ष्णेय ने कहा कि इस शोध में, पतंजलि शहद के 25 विभिन्न बैचों का उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से व्यापक परीक्षण किया गया।

पांच साल में 100 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा की थी, परंतु 2 साल में मात्र एक बना

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई नई घोषणा नहीं किए जाने की चर्चाएं विधानसभा के गलियारों में रही। भाजपा ने राजस्थान में चुनाव लड़ने पूर्व अपने मैनिफेस्टो में घोषण की थी कि, हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल में 100 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। परंतु राज्य सरकार के बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हुआ है। जबकि गत 2 बजट में सरकार ने 19 केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की थी।

ज्ञात रहे कि इन ''इंड्स्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स'' (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों) में महिलाओं समेत ऐसे युवाओं को सरकारी इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रशिक्षण देना था। ताकि इन लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके।

- राजस्थान में युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई बजट में

उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी छात्रों के साथ हुई चर्चा में कहा था कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं होते तो वह कौशल विकास मंत्रालय का पदभार संभालते। प्रधानमंत्री का यह कथन दर्शाता है कि वे युवाओं और महिलाओं के रोजगार व कौशल विकास को लेकर गंभीर है, और शायद इसी वजह से राजस्थान में भाजपा ने भी 100 इण्ड्स्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर (आई.टी.आई.) के निर्माण की घोषणा की थी। सरकार बनने के बाद बीते 2 वर्ष में 19 आईटीआई स्थापना की घोषणा भी गत बजटों में हुई। परंतु बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक सिर्फ 1 आई.टी.आई. का निर्माण कार्य ही पूरा हो सका है। शेष 18 में से कुछ जगहों पर तो अभी भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है।

बजट आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने 10 आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिन 10 आई.टी.आई. का निर्माण किया जाना था उनमें एक-एक केन्द्र का निर्माण डौगाना-नागौर, बारां, दौसा, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, सलूम्बर में निर्माण होना था और दो केन्द्रों का निर्माण जयपुर में किया जाना था। परन्तु अभी तक नागौर, जयपुर और बांसवाडा में केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि आवंटन भी नहीं हुआ है। वहीं बजट घोषणा 25-26 में 9 अन्य आई.टी.आई. निर्माण करने की घोषणा की थी, जिनमें से केवल एक का ही निर्माण हुआ है जो विद्याधर नगर जयपुर में स्थित है।

विकसित राजस्थान का विजन : चतुर्वेदी

जयपुर। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान बजट 2026-27 को समावेशी और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में गति देगा। चतुर्वेदी ने बताया कि बजट गरीब, युवा, किसान, नारी, मजदूर और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आधारभूत ढांचा, उद्योग विस्तार, कृषि व पशुपालन सशक्तीकरण और निवेश प्रोत्साहन से रोजगार सृजन को बल मिलेगा। बजट के तहत वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए नई भर्तियां, कौशल विकास और स्टार्टअप प्रोत्साहन, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रावधान भी शामिल हैं। ग्रीन बजट के माध्यम से सौर, पवन और जल ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करते हुए।

'व्यापारियों व उद्योगों के लिए नई दिशा'

जयपुर। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोर्टी) के कार्यकारी अध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अरूण अग्रवाल ने राजस्थान सरकार के बजट को व्यापारियों व उद्योगों को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में व्यापारियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली, व्यापार प्रोत्साहन नीति, और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इनसे व्यापार करना आसान होगा और व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे।

20 प्रतिशत घोषणाएं पूरी, 30 फीसदी शुरू भी नहीं हुई'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के तीसरे बजट को पूरी तरह नीरस और निराशाजनक करार देते हुए कहा कि सरकार घोषणाओं तक सीमित है, जमीनी क्रियान्वयन बेहद कमजोर है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने 2718 बजट घोषणाएं कीं, जिनमें से केवल 20 प्रतिशत ही पूरी हो पाई हैं। 30 प्रतिशत घोषणाएं अब तक शुरू नहीं हुईं, जबकि 40 प्रतिशत पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने दिखा रही है, जबकि वर्तमान समस्याओं की सुध लेने को तैयार नहीं है। रिफाइनरी शुरू करने की पूर्व घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली